नई खनन नीति के कारण डेढ़ साल में चार गुना पहुंचा राजस्व, केंद्र सरकार ने राजस्व बढ़ोतरी पर धामी सरकार की पीठ ठोकी

खनन का राजस्व 300 से 1200 करोड़ पहुंचा

देहरादून, विशेष संवाददाता। खनन विभाग अब राज्य के विकास में अहम भूमिका में आ गया। हाल में किए गए सुधार और सख्ती की वजह से डेढ़ साल की अवधि में खनन का राजस्व 300 करोड़ रुपये से बढ़कर 1200 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है।

शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजस्व में चार गुना बढ़ोतरी खनन सेक्टर में पारदर्शी और सतत निगरानी सिस्टम को लागू करने का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि राजस्व राज्य के विकास और जनकल्याणकारी योजना का स्वरूप भी तय करता है। राजस्व बढ़ने से लाभ यह हुआ है कि सरकार को विकास कार्य और आम लोगों के कल्याण की योजनाओं के लिए आवश्यक धन मिल रहा है।

धामी सरकार ने सितंबर 2024 को नई खनन नीति लागू की थी। इसमें अवैध खनन, राजस्व चोरी पर सख्ती से रोक लगाने के लिए कुछ नवाचार किए गए। साथ ही पुलिस- प्रशासन को भी अवैध खनन पर सख्ती दिखाने के निर्देश दिए। खनन निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सितंबर 2024 से पहले राज्य को खनन से सिर्फ 300 करोड़ रुपये सालाना राजस्व प्राप्त हो पाता था। अब यह राजस्व 1200 करोड़ रुपये के करीब आ गया है।

02 सौ करोड़ रुपये की विशेष सहायता मिल चुकी है उत्तराखंड को राजस्व में बढ़ोतरी पर

इन सुधारों से बदली राजस्व की तस्वीर

- ई नीलामी के जरिए खनन लॉट आवंटन
- खनन परिवहन के लिए माइनिंग सर्विलांस सिस्टम
- खनन गतिविधियों की डिजिटल ट्रैकिंग और निरीक्षण

> सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि खनन पर्यावरण के मानकों के अनुसार हो। इसके लिए एक ठोस पारदर्शी तंत्र विकसित किया गया। इससे राजस्व में शानदार वृद्धि हुई है। -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

उत्तराखंड को खनन सुधार लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हो चुका है। इसकी वजह से केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड के लिए ₹200 करोड़ की विशेष सहायता स्वीकृत की है।

टिहरी के कोटी कॉलोनी में शुक्रवार को एक्रो फेस्टिवल के समापन पर संबोधित करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। • हिन्दुस्तान

'युवाओं को स्वरोगार से जोड़ रही प्रदेश सरकार'

नई टिहरी, संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। टिहरी झील के विकास से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित चार दिवसीय टिहरी एक्रो फेस्टिवल और नेशनल एसआईवी चैंपियनशिप के समापन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बात कही। एसआईवी नेशनल चैंपियनशिप में उत्तरकाशी के कपिल नौटियाल विजेता बने। उन्हें मुख्यमंत्री ने तीन लाख रुपये का चेक प्रदान किया।

11 देशों के 25 और भारत के 57 पायलट्स ने टिहरी झील और आसपास के क्षेत्र में टेंडम इनफिनिटी टर्बलिंग, स्काई जंप, बेस जंपिंग और पैराग्लाइडिंग के करतब दिखाए।

वनाग्नि और बाढ़ से निपटने को अफसर कसें कमर: धामी

देहरादून, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग को वनाग्नि की रोकथाम के लिए ठोस इंतजाम करने के निर्देश दिए।

शुक्रवार को सचिवालय में नदियों की सुरक्षा और सिल्ट की सफाई के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग को मानसून के दौरान पैदा होने वाली बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा।

मालूम हो कि राज्य में फॉरेस्ट फायर सीजन 15 फरवरी से शुरू हो जाता है। सीएम ने वन विभाग को वन पंचायतों और वन क्षेत्र के आस-पास के लोगों के साथ तालमेल बनाए रखने को कहा।

कश्मीरियों से मारपीट पर राजनीतिक रंग न दें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकासनगर में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ मारपीट के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस घटना को राजनीतिक रंग कतई नहीं दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि है। यहां सभी का स्नेह और सम्मान से स्वागत किया जाता है। सभी के लिए समान अधिकार हैं। जाति-धर्म पूछकर कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले इसी प्रकार एंजेल चकमा मामले में भी राजनीति घोलने की साजिश की गई थी।

सड़क सुरक्षा- सौंग बांध को 176.91 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सड़क सुरक्षा, सौंग बांध निर्माण, आपदा राहत कार्यों समेत विभिन्न योजनाओं के लिए 195 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी। निर्माणाधीन सौंग बांध पेयजल परियोजना के अवस्थापना निर्माण कार्यों के लिए 103 .80 करोड़ रुपये, सड़क सुरक्षा के लिए 73 .11 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। सभी जिलों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों में वर्चुअल कंप्यूटर लैब की स्थापना को 4 .83 करोड़ तथा फॉरेंसिक वर्कस्टेशन के लिए 4 .30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।